



Prime Reader

CHASE YOUR VISION & DREAMS



**February
2024**

GA BOOSTER
Weekly
PDF



www.primereader.co.in

- BANK
- SSC
- UPSC
- RAILWAY
- SBI
- IBPS



website : www.primereader.co.in
contactus : support@primereader.co.in

Telegram : PrimeReader

General Awareness Topic(Covered)

- National
- International
- Banking & Finance
- Awards & Recognitions
- Sports
- Economy & Business
- Appointments & Resignation
- Defence
- Books & Authors
- Important Days
- Index & Reports
- Science & Technology
- Govt Scheme
- Obituary
- Committee & meeting
- Summit
- Environment
- MOU
- Acquisition & Mergers



Our paid course services

- Weekly Reading
 - Pdf Download
 - Mock Test
- Monthly Reading
 - Pdf Download
 - Mock Test
- Topic- Wise Reading
 - Pdf Download
 - Mock Test
- Exam Oriented Reading
 - Pdf Download
 - Mock Test
- Daily Current Affairs
 - Daily Mock Test
 - Pdf Download
- News Topic Wise
- One Liner Weekly
- One Liner Monthly
- One Liner Quarterly
- One Liner Half Yearly
- Pdf Hub (Unlimited Download)
- Software Technology System (Auto News Analysis)
- मॉक Mock Test

Visit on : www.primereader.co.in
Telegram : [PrimeReader](https://t.me/PrimeReader)
Contactus : support@primereader.co.in
70 4444 2011

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीकृत "किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल", कृषि-बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत कृषक समुदाय के लिए केंद्रीकृत "किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल", कृषि-बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, सचिव श्री मनोज आहूजा भी उपस्थित थे। 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत में किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल रही है, जो उन्हें फसल बीमा के माध्यम से प्रकृति की अप्रत्याशितता से बचाती है। इस योजना के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो गया कि किसान दावा प्रक्रिया को नेविगेट कर सकें, शिकायतें प्रस्तुत कर सकें, अपने प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और बिना किसी कठिनाई के समय पर सहायता प्राप्त कर सकें। इन चुनौतियों का समाधान करने और किसानों के लिए त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) 14447 शुरू की है। YES-Tech, Digi-Claim, WINDS, CROPIC और AIDE ऐप जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के साथ शुरू की गई ये पहल, खेती में नवाचार और स्थिरता के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

एमएसएमई क्षेत्र में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने डिजीरेडी सर्टिफिकेशन (DRC) पोर्टल लॉन्च किया। एमएसएमई क्षेत्र में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने डिजीरेडी सर्टिफिकेशन (DRC) पोर्टल लॉन्च किया। पहल के लिए, QCI, ONDC के साथ मिलकर, MSME संस्थाओं की डिजिटल तैयारी का आकलन और प्रमाणित करना है। इस ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन उपकरण का लाभ उठाकर, एमएसएमई ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के रूप में निर्बाध रूप से शामिल होने के लिए अपनी तैयारियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे उनकी डिजिटल क्षमताओं और व्यावसायिक क्षमता का विस्तार हो सकता है। DRC पोर्टल को सुव्यवस्थित विक्रेता यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एमएसएमई और छोटे खुदरा विक्रेता मौजूदा डिजिटल वर्कफ्लो में निर्बाध रूप से एकीकृत हो सकें।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने "महिलाओं के लिए विज्ञान-एक प्रौद्योगिकी और नवाचार (SWATI)" पोर्टल लॉन्च किया।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने "महिलाओं के लिए विज्ञान-एक प्रौद्योगिकी और नवाचार (SWATI)" पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA), नई दिल्ली में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पोर्टल लॉन्च करते हुए, स्वाति पोर्टल का डेटाबेस लिंग-अंतर की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्माण में काम आएगा। पोर्टल एक पूर्ण इंटरैक्टिव डेटाबेस है और भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जिसे डॉ सुभ्रा चक्रवर्ती के नेतृत्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (NIPGR), नई दिल्ली द्वारा विकसित, होस्ट और रखरखाव किया गया है।

फिनलैंड के पूर्व प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर स्टब चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो को हराने के बाद नॉर्डिक देश के 13वें राष्ट्रपति बने।

फिनलैंड के पूर्व प्रधान मंत्री अलेक्जेंडर स्टब चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो को हराने के बाद नॉर्डिक देश के 13वें राष्ट्रपति बने। कंजर्वेटिव नेशनल कोएलिशन पार्टी के स्टब को 51.6% वोट मिले, जबकि ग्रीन पार्टी के हाविस्टो को 48.4% वोट मिले। 55 वर्षीय स्टब, जो 2014-2015 में प्रधान मंत्री थे और 2004 में यूरोपीय संसद में एक विधायक के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, 1917 में रूसी साम्राज्य से नॉर्डिक देश की आजादी के बाद फिनलैंड के 13वें राष्ट्रपति बनेंगे। हाविस्टो 2019-2023 में फिनलैंड के शीर्ष राजनयिक और नाटो में इसके प्रवेश के मुख्य वार्ताकार थे।

लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को उनके साथियों द्वारा 6 फरवरी 2024 से तीन साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का अध्यक्ष चुना गया।

लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को उनके साथियों द्वारा 6 फरवरी 2024 से तीन साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रपति सलाम 6 फरवरी 2018 से अदालत के सदस्य हैं। अदालत में शामिल होने से पहले, वह जुलाई 2007 से दिसंबर 2017 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि थे। वह अमेरिकी न्यायाधीश जोन ई. डोनोपू का अनुसरण करते हैं, जो 2021 से 5 फरवरी 2024 तक राष्ट्रपति थे।

महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य करने के साथ-साथ एक महीने के लिए अतिरिक्त प्रभार के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सचिव का पद संभाल रहे थे। वरिष्ठ नौकरशाह संजय जाजू को चंद्रा के स्थान पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) सचिव का नया सचिव नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी जाजू वर्तमान में अपने कैडर राज्य तेलंगाना में कार्यरत हैं।

कजाख राष्ट्रपति कासिम-झोमार्ट तोकाएव ने सरकार को बर्खास्त करने के ठीक एक दिन बाद अपने प्रशासन के पूर्व प्रमुख और भ्रष्टाचार विरोधी निगरानीकर्ता ओल्ज़ास बेक्टेनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया है।

कजाख राष्ट्रपति कासिम-झोमार्ट तोकाएव ने सरकार को बर्खास्त करने के ठीक एक दिन बाद अपने प्रशासन के पूर्व प्रमुख और भ्रष्टाचार विरोधी निगरानीकर्ता ओल्ज़ास बेक्टेनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया है। बेक्टेनोव, जो पहले टोकाएव के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत थे और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी का नेतृत्व करते थे, अलीखान स्माइलोव का स्थान लेंगे। उनकी नियुक्ति स्माइलोव के कार्यकाल के मद्देनजर हुई है, जो देश की सबसे उथल-पुथल वाली स्वतंत्रता-युग की अशांति के बीच दो साल तक चली, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 238 मौतें हुईं। जनवरी 2022 में हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर स्माइलोव को प्रधान मंत्री नामित किया गया था, जिसमें 225 लोग मारे गए थे।

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मियो ओका को भारत के लिए अपना नया देश निदेशक नियुक्त किया है, वह ताकेओ कोनिशी का स्थान लेंगे, जिन्हें मनीला मुख्यालय में दक्षिण एशिया के लिए एडीबी महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मियो ओका को भारत के लिए अपना नया देश निदेशक नियुक्त किया है, वह ताकेओ कोनिशी का स्थान लेंगे, जिन्हें मनीला मुख्यालय में दक्षिण एशिया के लिए एडीबी महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। वह भारत में एडीबी संचालन के संचालन और सरकार और देश के अन्य विकास भागीदारों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी संभालेंगी। वह एडीबी की देश साझेदारी रणनीति, 2023-2027 के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगी, जिसे भारत में मजबूत और समावेशी निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले विकास को उत्प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक जापानी नागरिक, सुश्री ओका के पास लगभग 3 दशकों का पेशेवर अनुभव है, जिसमें एडीबी के साथ 18 वर्षों से अधिक का अनुभव शामिल है, जहां उन्होंने 2005 में मेकांग विभाग में एक परियोजना विशेषज्ञ के रूप में शामिल होने के बाद से विभिन्न क्षमताओं में काम किया है।

आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव, अतिरिक्त निदेशक जीएसटी, को भारत सरकार की एक प्रमुख पहल, द फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।

आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव, अतिरिक्त निदेशक जीएसटी, को भारत सरकार की एक प्रमुख पहल, द फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। नरेंद्र कुमार यादव सबसे कम उम्र के आईआरएस अधिकारी हैं जिन्हें 2009 में 22 साल की उम्र में नियुक्त किया गया था। नरेंद्र यादव, जो सार्वजनिक सेवा के प्रति अपने जुनून, प्रतिबद्धता और दृढ़ समर्पण के लिए जाने जाते हैं, ने अक्सर अपने प्रेरणादायक भाषणों के माध्यम से इच्छुक सिविल सेवकों को प्रेरित और सलाह दी है।

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बोर्ड ने वेंकटचलम एच. को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, जो IRDAI से नियामक अनुमोदन के अधीन है।

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बोर्ड ने वेंकटचलम एच. को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, जो IRDAI से नियामक अनुमोदन के अधीन है। वेंकटचलम एच. वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक, नवीन ताहिलयानी का स्थान लेंगे, जो टाटा समूह में एक अन्य भूमिका में चले गए हैं और उन्हें टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्हें बिक्री और वितरण, रणनीति, व्यवसाय और प्रक्रिया विकास और मुख्य खाता प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल है। वह 2016 में टाटा एआईए में शामिल हुए और अपनी पिछली भूमिका में अध्यक्ष और मुख्य वितरण अधिकारी थे।

अल साल्वाडोर के निवर्तमान राष्ट्रपति नायब बुकेले ने मध्य अमेरिकी देश में हुए चुनावों में लगातार दूसरी बार फिर से चुनाव जीता।

अल साल्वाडोर के निवर्तमान राष्ट्रपति नायब बुकेले ने मध्य अमेरिकी देश में हुए चुनावों में लगातार दूसरी बार फिर से चुनाव जीता। राष्ट्रपति बुकेले की जीत को उनकी उग्र गिरोह कार्रवाई के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है जिसने देश में नागरिकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। 24 जुलाई 1981 को जन्मे बुकेले को अक्सर 'दुनिया का सबसे कूल तानाशाह' कहा जाता है, यह टैग उन्हें सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स से मिला है। एक पूर्व प्रचारक, बुकेले ने पहले मई 2015 से अप्रैल 2018 तक सैन साल्वाडोर के मेयर के रूप में कार्य किया था।

एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट (LIC AMC) ने रवि कुमार झा को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।

एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट (LIC AMC) ने रवि कुमार झा को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। झा ने एलआईसी के साथ 30 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है और विभिन्न पदों को संभाला है। वह दिसंबर 2023 तक कंपनी में कॉर्पोरेट रणनीति के कार्यकारी के रूप में कार्यरत थे। झा के पास रांची विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है।

यूके की फ़ोटोग्राफ़र नीमा सरीखानी ने एक छोटे से हिमखंड पर शांति से सोते हुए एक प्यारे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर पीपुल्स च्वाइस अवार्ड जीता है।

यूके की फ़ोटोग्राफ़र नीमा सरीखानी ने एक छोटे से हिमखंड पर शांति से सोते हुए एक प्यारे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्डलाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर पीपुल्स च्वाइस अवार्ड जीता है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के निदेशक डॉ डगलस गूर द्वारा तस्वीर को "लुभावनी और मार्मिक" बताया गया था। पीपुल्स च्वाइस अवार्ड में रिकॉर्ड तोड़ 75,000 वोट पड़े, जिससे सारीखानी को 24 अन्य फाइनेलिस्टों पर जीत हासिल हुई। इन 25 फाइनेलिस्टों को लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और एक अंतरराष्ट्रीय निर्णायक पैनल द्वारा लगभग 50,000 प्रस्तुत तस्वीरों में से चुना गया था।

महान धावक और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SJFI) और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन (DSJA) द्वारा नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 'लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

महान धावक और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SJFI) और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन (DSJA) द्वारा नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 'लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुश्री उषा को उनके शानदार खेल करियर का सम्मान करने के लिए एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह में सम्मानित अतिथि श्री राजीव शुक्ला, संसद सदस्य - राज्यसभा और उपाध्यक्ष, बीसीसीआई और पूर्व भारतीय निशानेबाज श्री जसपाल राणा उपस्थित थे।

टेलर स्विफ्ट ने "मिडनाइट्स" के लिए ग्रैमी अवार्ड्स में चौथी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम जीता।

टेलर स्विफ्ट ने "मिडनाइट्स" के लिए ग्रैमी अवार्ड्स में चौथी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम जीता। वह ग्रैमी इतिहास में चार बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम जीतने वाली पहली व्यक्ति हैं। वह पहले इस रिकॉर्ड के लिए स्टीवी वंडर, फ्रैंक सिनात्रा और पॉल साइमन के साथ बराबरी पर थीं। स्विफ्ट को यह पुरस्कार सेलीन डायोन द्वारा प्रदान किया गया।

एचडीएफसी बैंक ने अपने पहले स्थायी वित्त बांड इश्यू में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं।

एचडीएफसी बैंक ने अपने पहले स्थायी वित्त बांड इश्यू में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। यह रेगुलेशन एस बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन डॉलर की कुल बढ़ोतरी का हिस्सा है। 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्थायी वित्त बांड अमेरिकी खजाने पर 0.95 प्रतिशत के प्रसार पर तीन साल की अवधि के लिए जुटाए गए हैं, जबकि शेष 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अमेरिकी राजकोष पर 1.08 प्रतिशत पर पांच वर्षों में चुकाया जाएगा। ये किसी भारतीय जारीकर्ता द्वारा तीन साल के स्थायी बांड और यूएसडी रेग एस जारी करने के समान आकार के लिए पांच साल के वरिष्ठ असुरक्षित बांड के लिए हासिल किया गया सबसे सख्त क्रेडिट स्प्रेड है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने CRISIL के फंड ऑफ़ फंड्स फ़ॉर स्टार्टअप्स (FFS) अध्ययन रिपोर्ट के प्रभाव मूल्यांकन को "प्रभाव" नाम से जारी किया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने CRISIL के फंड ऑफ़ फंड्स फ़ॉर स्टार्टअप्स (FFS) अध्ययन रिपोर्ट के प्रभाव मूल्यांकन को "प्रभाव" नाम से जारी किया है। यह स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ़ फंड्स (FFS) के प्रभाव का आकलन करता है। 2016 में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टार्ट अप इंडिया एक्शन प्लान के तहत फंड ऑफ़ फंड फ़ॉर स्टार्ट अप्स (FFS) DPIIT, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना का प्रबंधन DPIIT की ओर से और उसके समग्र मार्गदर्शन और निर्देशन में SIDBI द्वारा किया जा रहा है। इस योजना ने पहले ही 938 अद्वितीय स्टार्टअप्स में निवेश किए गए ₹17,534 करोड़ के साथ निकाली गई राशि का लगभग 4 गुना निवेश उत्प्रेरित किया है। इस प्रकार, इस योजना के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ा, जिससे इस क्षेत्र में पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई। जबकि एफएफएस मुख्य रूप से युवा कंपनियों में शुरुआती चरण की फंडिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, इसके 18 स्टार्टअप पहले ही यूनिकॉर्न बन चुके हैं।

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के 650 किलोमीटर (किमी) लंबे मुख्य प्रवाह के साथ बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के 650 किलोमीटर (किमी) लंबे मुख्य प्रवाह के साथ बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह परियोजना एडीबी-वित्तपोषित असम एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (2010-2020) और बांग्लादेश में इसी तरह के निवेश की सफलता और सबक पर आधारित है और ब्रह्मपुत्र नदी में बार-बार आने वाली बाढ़ और निरंतर नदी तट कटाव से निपटना जारी रखेगी। यह परियोजना जलवायु और आपदा resilience और खाद्य सुरक्षा के लिए

समर्थन को तेज करते हुए बाढ़ और नदी तट के कटाव जोखिम प्रबंधन और इसकी दीर्घकालिक योजना में निवेश को बढ़ाने के लिए एक समग्र, एकीकृत और जोखिम-सूचित दृष्टिकोण लागू करेगी। आपदा प्रतिरोधी आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सह-लाभों को अनुकूलित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने से, परियोजना से लगभग 1 मिलियन लोगों को लाभ होगा और 50,000 हेक्टेयर से अधिक फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।

भारत ने श्रीलंका और मॉरीशस में अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू की हैं।

भारत ने श्रीलंका और मॉरीशस में अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, इस पहल के हिस्से के रूप में मॉरीशस में RuPay कार्ड सेवाएं शुरू की गईं। श्रीलंका में पहला यूपीआई लेनदेन एक भारतीय द्वारा किया गया था, जिसमें मॉरीशस के प्रधान मंत्री प्रविंद जुगनैथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ-साथ भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी आभासी समारोह में शामिल हुए थे। यूपीआई के लॉन्च से श्रीलंका और मॉरीशस के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं, जिससे श्रीलंका और मॉरीशस जाने वाले भारतीयों के साथ-साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरीशस नागरिकों के लिए लेनदेन आसान हो गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा गैर-कार्यकारी निदेशकों (NED) के पारिश्रमिक की सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख प्रति वर्ष कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा गैर-कार्यकारी निदेशकों (NED) के पारिश्रमिक की सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख प्रति वर्ष कर दिया है। बैंक का बोर्ड बैंक के आकार, एनईडी के अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर 30 लाख रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर कम राशि तय कर सकता है। NED को दिए गए निश्चित पारिश्रमिक की समीक्षा के निर्देश छोटे वित्त बैंकों (SFB) और भुगतान बैंकों (PB) सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे। निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

कम ब्याज दर वाले ऋण वाले किसानों और व्यापारियों को समर्थन देने के लिए, वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) और पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कम ब्याज दर वाले ऋण वाले किसानों और व्यापारियों को समर्थन देने के लिए, वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) और पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। MoU का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट (e-NWR) के खिलाफ फंडिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। NWR प्रणाली किसानों को अपने खेतों के पास गोदामों में उपज को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से संग्रहीत करने में सक्षम

बनाती है। यह किसानों को उनके जमा स्टॉक के विरुद्ध जारी NWR का उपयोग करके बैंकों से ऋण प्राप्त करने की भी अनुमति देता है। किसान 75 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य श्रेणियों के उधारकर्ता कृषि क्षेत्र के तहत 5 करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। MoU का आदान-प्रदान 5 फरवरी, 2024 को पीएसबी के प्रधान कार्यालय में WDRA के अध्यक्ष टीके मनोज कुमार और पीएसबी के एमडी और सीईओ स्वरूप कुमार साहा के बीच हुआ। PSB के कार्यकारी निदेशक डॉ. राम जस यादव और रवि मेहरा, उप निदेशक (M&C) नवीन बरोलिया और WDRA के सहायक निदेशक (SA&O) साई प्रदीप गोपीसेट्टी की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए।

फिनटेक स्टार्टअप LeRemitt और यस बैंक ने एक क्रॉस-बॉर्डर प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए साझेदारी की है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को अमेरिकी डॉलर और यूरो सहित प्रमुख मुद्राओं में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने में सक्षम बनाता है।

फिनटेक स्टार्टअप LeRemitt और यस बैंक ने एक क्रॉस-बॉर्डर प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए साझेदारी की है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को अमेरिकी डॉलर और यूरो सहित प्रमुख मुद्राओं में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने में सक्षम बनाता है। बहु-मुद्रा समर्थन के अलावा, मंच वैश्विक व्यापार में शामिल छोटे व्यवसायों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और लागत लाभ प्रदान करता है, जिससे यह एमएसएमई के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। यह सहयोग एक निर्बाध, कुशल और लागत प्रभावी अंतरराष्ट्रीय भुगतान समाधान प्रदान करके एमएसएमई को सशक्त बनाने के समर्पण पर प्रकाश डालता है।

हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (HSBC) ने तेजी से बढ़ती जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों को वित्तपोषित करने के लिए Google क्लाउड के साथ साझेदारी की है।

हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (HSBC) ने तेजी से बढ़ती जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों को वित्तपोषित करने के लिए Google क्लाउड के साथ साझेदारी की है। नई साझेदारी के तहत, Google क्लाउड उद्यम ऋण वित्तपोषण विकल्पों का पता लगाने के लिए GCR-सस्टेनेबिलिटी कंपनियों को एचएसबीसी की विशेषज्ञ जलवायु तकनीक वित्त टीम से परिचित कराएगा। HSBC \$1 बिलियन के जलवायु तकनीकी वित्त को तैनात करने के साथ-साथ HSBC के ग्राहक आधार के साथ कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की अपनी महत्वाकांक्षा के हिस्से के रूप में, GCR-सस्टेनेबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कंपनियों के लिए वित्तपोषण के अवसरों की तलाश करेगा।

अहमदाबाद स्थित रियल एस्टेट डेवलपर शिवालिक ग्रुप को अपने पहले फंड- शिवालिक इन्वेस्टमेंट फंड के लिए श्रेणी II AIF (वैकल्पिक निवेश फंड) के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) से विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

अहमदाबाद स्थित रियल एस्टेट डेवलपर शिवालिक ग्रुप को अपने पहले फंड- शिवालिक इन्वेस्टमेंट फंड के लिए श्रेणी II AIF (वैकल्पिक निवेश फंड) के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) से विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित AIF का लक्ष्य निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 300 करोड़ रुपये तक जुटाना है, जिसमें निवेश प्रबंधक के विवेक पर 150 करोड़ रुपये का ग्रीन शू विकल्प भी शामिल है। यह फंड भारत में व्यक्तियों, पारिवारिक कार्यालयों, एचयूएफ, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों, निजी संस्थानों, अन्य कॉर्पोरेट निकाय या गैर-कॉर्पोरेट सहित घरेलू निवेशकों के एक विविध समूह से धन जुटाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी छठी द्विमासिक नीति घोषणा के दौरान अपनी बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) 6.5% पर बनाए रखी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी छठी द्विमासिक नीति घोषणा के दौरान अपनी बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) 6.5% पर बनाए रखी। यह छठी बार था जब RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, और विशेष रूप से पूरे FY24 के लिए, रेपो दर 6.5% थी। इसके अलावा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी ने भी स्थायी जमा सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा दरों को क्रमशः 6.25% और 6.75% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया। विकास के मोर्चे पर, आरबीआई ने आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6.6% के पिछले अनुमान से 7% वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। इस अनुमान में Q1 में 7.2%, Q2 में 6.8%, Q3 में 7% और Q4 में 6.9% की वृद्धि दर शामिल है। इस बीच, वित्तीय वर्ष 2023-24 (Q2FY24) की दूसरी तिमाही में, जीडीपी वृद्धि विश्लेषकों की उम्मीदों से अधिक होकर 7.6% तक बढ़ गई।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) को गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिल गई है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) को गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, सहायक कंपनी न केवल IREDA के लिए अपने वैश्विक पदचिह्न छोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी फंडिंग हासिल करने के लिए एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगी। IFSC में IREDA के प्रवेश से नए व्यावसायिक अवसर खुलने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में IREDA की वैश्विक उपस्थिति स्थापित होने की उम्मीद है।

फिनटेक फर्म Juspay और Decentro और सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस कंपनी Zoho को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है।

फिनटेक फर्म Juspay और Decentro और सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस कंपनी Zoho को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। वे रेजरपे, कैशफ्री, ज़ोमैटो और अन्य कंपनियों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें पहले लाइसेंस मिला था। जबकि Juspay एक भुगतान गेटवे के रूप में काम करता है जो ईकॉमर्स भुगतान के लिए एक प्रौद्योगिकी स्टैक चलाता है, Decentro एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो ईकॉमर्स और अन्य उपभोक्ता-सामना करने वाले खिलाड़ियों को ऋण, केवाईसी और अन्य सेवाओं जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है। एक सेवा स्टार्टअप के रूप में सॉफ्टवेयर ज़ोहो को 2 फरवरी, 2024 को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस भी मिल गया। ज़ोहो आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइज SaaS कंपनी है।

विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए भुगतान को आसान बनाने के लिए एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) ने फ्लाइवायर के साथ समझौता किया।

विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए भुगतान को आसान बनाने के लिए एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) ने फ्लाइवायर के साथ समझौता किया। छात्रों को एक सहज और पूरी तरह से डिजिटल भुगतान अनुभव दिया जाएगा, जो मौजूदा जटिल प्रक्रिया से बेहतर है। साझेदारी के तहत, फ्लाइवायर की तकनीक को सीधे बैंक के प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जाएगा, जिससे भारतीय छात्रों को उनके अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक भुगतान के लिए एक उन्नत डिजिटल चेकआउट अनुभव प्रदान किया जाएगा। इस साझेदारी के तहत, सेवाएं आवेदन से लेकर ट्यूशन फीस तक होंगी।

अपने कार्ड व्यवसाय का विस्तार करने और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (SME) तक पहुंचने के प्रयास में, एचडीएफसी बैंक ने चार क्रेडिट कार्ड पेश किए- BizFirst, BizGrow, BizPower और BizBlack

अपने कार्ड व्यवसाय का विस्तार करने और छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (SME) तक पहुंचने के प्रयास में, एचडीएफसी बैंक ने चार क्रेडिट कार्ड पेश किए। चार क्रेडिट कार्ड बिज़फ़र्स्ट, बिज़ग्रो, बिज़पावर और बिज़ब्लैक हैं। बिजनेस क्रेडिट कार्ड रेंज 55 दिनों का ब्याज मुक्त क्रेडिट चक्र प्रदान करती है, उपयोगिता बिल, जीएसटी, आयकर, विक्रेता भुगतान, व्यापार यात्रा और व्यापार उत्पादकता उपकरण जैसे मुख्य व्यावसायिक खर्चों पर बचत करती है। एचडीएफसी बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बिजनेस क्रेडिट कार्ड की मुख्य विशेषताएं: 55 दिनों तक निःशुल्क क्रेडिट अवधि (उद्योग में सर्वोत्तम); व्यावसायिक खर्च पर 10X* तक रिवाइड पॉइंट; बिल भुगतान | कर भुगतान | विक्रेता भुगतान | व्यापार यात्रा | व्यवसाय उत्पादकता उपकरण; विशेष रूप से तैयार व्यवसाय बीमा पैकेज; आग और चोरी | सुरक्षित और पारगमन में नकदी |

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; विशिष्ट व्यवसाय केंद्रित मोचन कैटलॉग; यात्रा एवं होटल | माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 | स्पष्ट कर | बिज़नेस के लिए अमेज़न | गूगल विज्ञापन; कार्ड पर ईएमआई और लोन की सुविधा।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने एक नई निवेश योजना- LIC इंडेक्स प्लस प्लान लॉन्च की है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने एक नई निवेश योजना- LIC इंडेक्स प्लस प्लान लॉन्च की है। यह योजना नियमित प्रीमियम के साथ एक यूनिट-लिंक्ड, व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना है। यह योजना पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान जीवन बीमा कवरेज के साथ-साथ बचत का लाभ भी प्रदान करती है। यह योजना पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान जीवन बीमा कवरेज और बचत प्रदान करती है। इस पॉलिसी के तहत बीमा कराने की न्यूनतम आयु 90 दिन है। अधिकतम आयु 85 वर्ष रखी गई है। प्रीमियम मूल बीमा राशि के अनुसार तय किया जाएगा। 90 दिन से 50 वर्ष की आयु के बीमाकर्ताओं के लिए बीमा राशि वार्षिक प्रीमियम का 7 से 10 गुना रखी गई है। यह 90 दिन से 50 साल तक के लोगों के लिए होगा। जबकि 51 से 60 वर्ष की आयु वालों के लिए वार्षिक प्रीमियम बीमा राशि का 7 गुना होगा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तीन दिवसीय, पहले "विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन" के समापन सत्र में द हिंदू ग्रुप द्वारा लाई गई एक कॉफी-टेबल पुस्तक "श्री जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स" का विमोचन किया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तीन दिवसीय, पहले "विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन" के समापन सत्र में द हिंदू ग्रुप द्वारा लाई गई एक कॉफी-टेबल पुस्तक "श्री जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स" का विमोचन किया। यह पुस्तक, जो हिंदुओं के चार पवित्र धामों में से एक, पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सहोदर देवताओं से जुड़ी परंपराओं और रीति-रिवाजों का सचित्र वर्णन करती है, का अनावरण द हिंदू बिजनेसलाइन के संपादक रघुवीर श्रीनिवासन की उपस्थिति में किया गया। जिन्होंने श्रीजगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स और टीएचजी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के एसएंडडी सर्कुलेशन के उपाध्यक्ष श्रीधर अरनाला का संपादन भी किया है। यह चित्र-समृद्ध कॉफी-टेबल पुस्तक श्री जगन्नाथ पूजा, मंदिर और इसकी परंपराओं की कहानी बताने का प्रयास करती है।

सूचना और प्रसारण सचिव, संजय जाजू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया।

सूचना और प्रसारण सचिव, संजय जाजू ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। श्री जाजू ने प्रभाग के नवीनतम प्रकाशनों 'इंडिया ईयर बुक 2024' और 'कैरियर कॉलिंग' का भी अनावरण किया। 'इंडिया ईयर बुक 2024', वार्षिक संदर्भ मार्गदर्शिका नवीनतम सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों को समाहित

करते हुए भारत की प्रगति की नब्ज पकड़ती है। इसके अलावा, 'करियर कॉलिंग' पारंपरिक से लेकर कम-ज्ञात रास्तों तक करियर की खोज करने वाला एक क्यूरेटेड संग्रह है।

आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2024-25 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वोट-ऑन-अकाउंट बजट पेश किया है।

आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2024-25 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वोट-ऑन-अकाउंट बजट पेश किया है। उद्योग मंत्री गुडिवाडा अमरनाथ ने इसे विधान परिषद में पेश किया। राजेंद्रनाथ ने राजस्व व्यय 2,30,110.41 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 30,530.18 करोड़ रुपये रखा है। राजकोषीय घाटा 55,817 करोड़ रुपये है जबकि राजस्व घाटा 24,758 करोड़ रुपये रखा गया है। राजकोषीय घाटे की दर लगभग 3.51 प्रतिशत है जबकि राजस्व घाटे की दर जीएसडीपी का 1.56 प्रतिशत है। मार्च 2023 में विशाखापत्तनम में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप निवेश के माध्यम से 13,11,000 करोड़ रुपये लाने के लिए 386 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व व्यय का संशोधित अनुमान 2,28,237.77 करोड़ रुपये है, जबकि पूंजीगत व्यय के लिए यह 27,308.12 करोड़ रुपये है। 2023-24 के लिए राजस्व घाटा लगभग 31,534.94 करोड़ रुपये है, जबकि इसी अवधि के लिए राजकोषीय घाटा लगभग 60,153.59 करोड़ रुपये है, जो जीएसडीपी का क्रमशः 2.19 प्रतिशत और 4.18 प्रतिशत है।

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने में ₹1,067 करोड़ और अतिरिक्त व्यय में ₹1,420 करोड़ के हिसाब के बाद ₹273.94 करोड़ के घाटे का प्रस्ताव रखा गया।

केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने में ₹1,067 करोड़ और अतिरिक्त व्यय में ₹1,420 करोड़ के हिसाब के बाद ₹273.94 करोड़ के घाटे का प्रस्ताव रखा गया।

अधिकांश कर मर्दों और कल्याण पेंशन का मुख्य विषय अछूता था, जबकि शुल्क/लेवी को संशोधित किया गया था, और आईएमएफएल पर 10 रुपये प्रति लीटर का गैलन शुल्क नए सिरे से पेश किया गया था। वित्त मंत्री ने "वित्तीय बाधाओं के बावजूद" रबर का समर्थन मूल्य ₹10 बढ़ाकर ₹180 कर दिया। केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, केरल की पात्र उधार सीमा ₹39,626 करोड़ है, जिसके आधार पर राज्य का बजट तैयार किया गया था। लेकिन उसे अब तक केवल 28,830 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी गई है। बालगोपाल ने ₹24 करोड़ जुटाने के लिए 1.2 पैसे प्रति यूनिट की दर से एकत्रित बिजली शुल्क को 15 पैसे प्रति यूनिट तक संशोधित करने का प्रस्ताव रखा। इसे बढ़ाकर 10 पैसे प्रति यूनिट किया जाएगा, जिससे अतिरिक्त 101.41 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। इसके लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण राशि का 0.1 प्रतिशत और

अधिकतम 10,000 रुपये का फाइलिंग शुल्क लिया जाएगा। इससे ₹50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है।

गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 3.32 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया, जिसमें लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया।

गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 3.32 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया, जिसमें लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया। 2024-25 के लिए ₹3,32,465 करोड़ के कुल बजट परिव्यय में पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24 बजट अनुमान) की तुलना में ₹31,444 करोड़ या 10.44% की वृद्धि देखी गई। कुल परिव्यय में से, लगभग ₹2.14 लाख करोड़ या 64.4% "विकासात्मक व्यय" के लिए आवंटित किया गया था, जबकि ₹83,000 करोड़ या 25.1% "गैर-विकासात्मक व्यय" के लिए था। गुजरात सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप की रूपरेखा तैयार करते हुए ₹146.72 करोड़ के अनुमानित अधिशेष बजट के साथ वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वित्तीय योजना का अनावरण किया। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में गुजरात का योगदान 2000-2001 में 5.1% से बढ़ाकर अब 8.2% करके, राज्य ने भारत का विकास इंजन होने का गौरव अर्जित किया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वार्षिक बजट को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें 8,811 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी परिव्यय निर्धारित किया गया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वार्षिक बजट को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें 8,811 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी परिव्यय निर्धारित किया गया है। केंद्र के जोर के अनुरूप, पूंजीगत व्यय वार्षिक आवंटन का 61 प्रतिशत (लगभग) होता है। चालू वित्त वर्ष में DDA की कुल प्राप्तियां पिछले वर्ष के 4,392 करोड़ रुपये की तुलना में 75 प्रतिशत की भारी उछाल के साथ 7,696 करोड़ रुपये हो गईं। इन परियोजनाओं के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित व्यय का वित्तपोषण राजस्व से किया जाएगा, जिसका अनुमान 9,182 करोड़ रुपये लगाया गया है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को 6.2% तक बढ़ा दिया है, जो पहले के अनुमान 6.1% से अधिक है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को 6.2% तक बढ़ा दिया है, जो पहले के अनुमान 6.1% से अधिक है। मुद्रास्फीति प्रबंधन के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2024 के मध्य से ब्याज दरों को कम करना शुरू करने और 2025 के अंत तक 5.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। 2025-26 के लिए, OECD ने भारत के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है।

अंतरिम बजट ने अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को 11.1 ट्रिलियन रखा है, जो वित्त वर्ष 24 के लिए 9.5 ट्रिलियन के संशोधित अनुमान से 17% अधिक है। 17% अनुमानित वृद्धि पांच वर्षों में सबसे कम है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Target) में ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा 70% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Target) में ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा 70% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से टारगेट में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। प्रस्तावित संयोजन के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता टारगेट में 51% हिस्सेदारी हासिल कर लेगा (ताजा विकास पूंजी और शेयर खरीद के संयोजन के माध्यम से)। उपरोक्त के अलावा, अधिग्रहणकर्ता एक निश्चित अवधि में लक्ष्य में 19% तक की अतिरिक्त हिस्सेदारी भी हासिल कर लेगा।

एचडीएफसी बैंक को छह बैंकों- एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक में 9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है।

एचडीएफसी बैंक को छह बैंकों- एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक में 9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। 'कुल होल्डिंग' में बैंक और समान प्रबंधन/नियंत्रण के तहत संस्थाओं, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी और प्रमोटर समूह संस्थाओं की शेयरधारिता शामिल है। 18 दिसंबर, 2023 को एचडीएफसी बैंक (समूह के प्रमोटर/प्रायोजक के रूप में) द्वारा आरबीआई को दिए गए आवेदनों के अनुसार मंजूरी दी गई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की है। EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 235वीं बैठक में 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की गई है। यह निर्णय वित्त वर्ष 2023 के लिए ब्याज दर में मामूली वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 2022 में 8.10% से बढ़कर 8.15% हो गया है, और वित्त वर्ष 2021 में 8.5% से वित्त वर्ष 2022 में 8.1% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए ईपीएफ सदस्यों के खातों में 1,07,000 करोड़ रुपये के अनुशंसित वितरण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज में अपना भुगतान शेयर 4.99% से बढ़ाकर 5.02% कर दिया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज में अपना भुगतान शेयर 4.99% से बढ़ाकर 5.02% कर दिया है। एक निवेशक के रूप में कार्य करते हुए एलआईसी ने हाल ही में एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के तीन लाख से अधिक शेयर खरीदे हैं। प्रति शेयर औसत लागत ₹716 थी।

बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड (BFHL) को एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 100% चुकता शेयर पूंजी हासिल करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से अधिग्रहण पर अंतिम मंजूरी मिल गई है।

बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड (BFHL) को एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 100% चुकता शेयर पूंजी हासिल करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से अधिग्रहण पर अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके साथ, प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए सभी विनियामक स्वीकृतियां लागू हो गई हैं।

केरल वन अनुसंधान संस्थान (KFRI), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने केरल से एक नई कवक प्रजाति, 'Trichoglossum syamviswanathii' की खोज की है।

केरल वन अनुसंधान संस्थान (KFRI), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने केरल से एक नई कवक प्रजाति, 'Trichoglossum syamviswanathii' की खोज की है। Trichoglossum syamviswanathii प्रजाति का नाम भारत में वानिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक और KFRI के पूर्व निदेशक स्याम विश्वनाथ के नाम पर रखा गया है। Trichoglossum प्रजातियाँ कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और वन अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Women and Girls in Science) हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है।

विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Women and Girls in Science) हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विज्ञान सभा में महिलाओं और लड़कियों का नौवां अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2015 को प्रस्ताव 70/212 पारित किया, जिसने फरवरी के 11वें दिन को वार्षिक स्मरणोत्सव के रूप में घोषित किया। विज्ञान में

महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय "Women and Girls in Science Leadership, a New Era for Sustainability" है।

विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है।

विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन समाज सुधारक और महान यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती का प्रतीक है। यह दिन भारत और दुनिया भर में यूनानी चिकित्सा के विकास में हकीम अजमल खान के योगदान को चिह्नित करता है। इसका उद्देश्य यूनानी दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। भारतीय सरकार ने यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास में उनके जबरदस्त योगदान को मान्यता देने के लिए हकीम अजमल खान के जन्मदिन को विश्व यूनानी दिवस के रूप में घोषित किया। 2017 में, पहला विश्व यूनानी दिवस हैदराबाद के केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (CRIUM) में मनाया गया। यूनानी दिवस 2024 का विषय "Unani Medicine for One Earth, One Health" है।

इसके पोषण मूल्य और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य से हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है।

इसके पोषण मूल्य और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य से हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में दालों के मूल्य को मान्यता दी और वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष (IYP) के रूप में अपनाने की प्रक्रिया शुरू की। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने इस दिन का उद्देश्य इसके पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के समापन के बाद, पश्चिम अफ्रीका में भूमि से घिरे देश बुर्किना फासो ने एक दिन को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने का विचार प्रस्तावित किया। आखिरकार, 2019 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में समर्पित किया। विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय 'Pulses: Nourishing soil and people' है।

देश के प्रत्येक बच्चे को कृमि मुक्त बनाने के लिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day or NDD) मनाया जाता है।

देश के प्रत्येक बच्चे को कृमि मुक्त बनाने के लिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day or NDD) मनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य 1 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मृदा-संचारित हेल्मिन्थ्स (STH) की व्यापकता से मुक्ति दिलाना है। एसटीएच को आम भाषा में परजीवी आंत्र कृमि भी कहा

जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2015 में स्थापित राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, भारत सरकार के तहत काम करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह दिन भारत के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 277 जिलों में मनाया जाता है।

अरेबियन तेंदुए की गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 फरवरी 2024 को दुनिया भर में पहली बार संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस मनाया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुए दिवस के रूप में चिह्नित किया है। संकल्प 77/295 में औपचारिक रूप दिया गया यह निर्णय, IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत अरेबियन तेंदुए (पैथेरा पाईस निम्र) की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डालता है। अरब तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य इस प्रजाति को संरक्षण के लिए एक प्रमुख के रूप में पुनर्स्थापित करना है, जो ग्रह के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के resilience को बनाए रखने में जैव विविधता की आवश्यक भूमिका को रेखांकित करता है।

महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation (FGM)) हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है।

महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation (FGM)) हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। 6 फरवरी 2024 को इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 13वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिन की थीम 'Her Voice. Her Future. Investing in Survivor-Led Movements to End Female Genital Mutilation' है। महिला जननांग विकृति (FGM) की प्रथा के खिलाफ, डब्ल्यूएचओ ने 1997 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया था। तब से FGM का प्रतिकार करने के लिए कई प्रयास किए गए। इस प्रथा के परित्याग में तेजी लाने के लिए 2007 में यूएनएफपीए और यूनिसेफ द्वारा महिला जननांग विकृति/काटने पर संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में महिला जननांग विकृति (FGM) के उन्मूलन पर एक प्रस्ताव A/RES/67/14 अपनाया।

भारत ने 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 32.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जो उन 36 सदस्य देशों की "सम्मान सूची" में शामिल हो गया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को समय पर अपने नियमित बजट का पूरा भुगतान कर दिया है।

भारत ने 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 32.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जो उन 36 सदस्य देशों की "सम्मान सूची" में शामिल हो गया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को समय पर अपने नियमित बजट का पूरा भुगतान कर दिया है। योगदान पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक, 36 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय नियमों में निर्दिष्ट 30 दिन की नियत अवधि के भीतर अपने नियमित बजट आकलन का पूरा भुगतान कर दिया है।

वर्ल्ड डिफेंस शो का दूसरा संस्करण 4 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था।

वर्ल्ड डिफेंस शो का दूसरा संस्करण 4 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रमाण देते हुए, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट चल रहे विश्व रक्षा शो (WDS) 2024 के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में रियाद की यात्रा पर थे। प्रदर्शनी में उद्योग के हर क्षेत्र और स्तर की रक्षा कंपनियां प्रचुर मात्रा में शो सुविधाओं के साथ शामिल हैं, जो आपको रक्षा समुदाय से जोड़ने वाले सर्वोत्तम श्रेणी के कार्यक्रम पेश करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। 06 फरवरी, 2024 को रक्षा राज्य मंत्री ने शो के मौके पर सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल-सऊद के साथ बैठक की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। श्री अजय भट्ट WDS 2024 के मौके पर म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड और उसके स्थानीय साझेदार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के भी गवाह बने।

टेक दिग्गज गूगल ने राज्य में प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित समाधान प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

टेक दिग्गज गूगल ने राज्य में प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित समाधान प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। सहयोग के एक भाग के रूप में, Google कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, स्थिरता, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में समाधान प्रदान करने के लिए अपनी AI क्षमताओं का लाभ उठाएगा। कंपनी ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), नागपुर में एक अत्याधुनिक AI उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने की भी घोषणा की। यह सहयोग राज्य के नागरिकों को महत्वपूर्ण भविष्य-तैयार कौशल के साथ सशक्त बनाएगा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे आवश्यक क्षेत्रों में क्रांति लाएगा, और आईआईआईटी नागपुर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से महाराष्ट्र एआई स्टार्टअप के लिए एक समृद्ध वातावरण तैयार करेगा। हेल्थकेयर क्षेत्र में, कंपनी, अपने साझेदारों और महाराष्ट्र राज्य के साथ, एआई-सक्षम स्क्रीनिंग के माध्यम से देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए टीबी-चेस्ट एक्स-रे और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे स्वास्थ्य संबंधी एआई इमेजिंग मॉडल प्रदान करेगी।

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में EdCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया।

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में EdCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया। सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय, श्री के. संजय मूर्ति; स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, श्री संजय कुमार; कार्यकारी निदेशक, एडसीआईएल, डॉ. चन्द्रशेखर; और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने एनवीएस के छात्रों के प्रयासों की सराहना की और उल्लेख किया कि लगभग 14,000 छात्र बिना किसी कोचिंग सेंटर में शामिल हुए आईआईटी, एनआईटी आदि सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल रहे हैं। कई छात्र हाशिये पर पड़े परिवारों से आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 70 छात्रों को 5 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

7 फरवरी 2024 को, उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित किया, जो कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

7 फरवरी 2024 को, उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित किया, जो कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह संविधान के अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) से उपजा है जो हालांकि लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी राज्य को इस तरह के एक समान कानून को लागू करने का प्रयास करने के लिए बाध्य करता है। विधेयक को अब राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। यूसीसी विधेयक, जो अब एक अधिनियम बन जाएगा, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत draft पर आधारित है। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत आदि के लिए एक सामान्य कानून लाती है, जो पहले हर धर्म के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते थे। सामान्य संहिता द्विविवाह (एक व्यक्ति से कानूनी तौर पर दूसरे व्यक्ति से विवाह करते हुए भी विवाह करना) और बहुविवाह (एक साथ कई पति-पत्नी रखना) पर रोक लगाती है।

तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड ने ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र) और कवल टाइगर रिजर्व (तेलंगाना) के बीच गलियारे क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के वन विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड ने ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र) और कवल टाइगर रिजर्व (तेलंगाना) के बीच गलियारे क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के वन विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, कागजनगर और

आसिफाबाद डिवीजनों में 1,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एक संरक्षण रिजर्व होगा, जिसमें सुरक्षा और संरक्षण के उपाय बढ़ जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में, वन्यजीवों के हमलों से होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को ₹5 लाख की पिछली राशि से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। बोर्ड ने दूरदराज के इलाकों में सेलफोन कनेक्टिविटी बढ़ाने की पहल का भी समर्थन किया, इस कदम से इन क्षेत्रों में संचार और सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। बोर्ड ने टी-फाइबर कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी, जो राज्य भर के वन क्षेत्रों के सभी गांवों और बस्तियों तक विस्तारित होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 फरवरी, 2024 को गोवा का दौरा किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 फरवरी, 2024 को गोवा का दौरा किया। उन्होंने ONGC Sea सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने विकसित भारत, विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में भाग लिया। ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना प्रधानमंत्री का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024, 6 से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन होगा, जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक साथ लाएगा, और भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने गोवा में सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा के स्थायी परिसर का राष्ट्र को उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दक्षिण गोवा में 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन किया। इसे 60 टीपीडी गीले कचरे और 40 टीपीडी सूखे कचरे के वैज्ञानिक उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि इसमें 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी है जो अधिशेष बिजली उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री ने पणजी और रीस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ यात्री रोपवे की आधारशिला रखी। उनके द्वारा दक्षिण गोवा में 100 एमएलडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति आदेश भी वितरित किए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे।

कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स (CITS) का मुख्यालय चीन से भारत में स्थानांतरित हो जाएगा।

कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स (CITS) का मुख्यालय चीन से भारत में स्थानांतरित हो जाएगा। यह निर्णय हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित एफएओ इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी (FAO IGG on Tea) के 25वें सत्र में लिया गया। चाय पर खाद्य और कृषि संगठन (FAO) IGG, जो संयुक्त राष्ट्र के अधीन है, ने भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उठाने और विश्व स्तर पर चाय बागानों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने का निर्णय लिया। चाय पर FAO IGG चाय के लिए

सर्वोच्च वैश्विक मंच है जहां सभी चाय उत्पादक और उपभोक्ता देश वैश्विक बाजार की स्थिति और अल्पकालिक दृष्टिकोण के नियमित मूल्यांकन सहित चाय के उत्पादन, उपभोग, व्यापार और कीमतों के रुझान पर विचार-विमर्श करते हैं। यह बैठक पहली बार असम में आयोजित की गई, जिसमें 31 जनवरी, 2024 से तीन दिनों तक चलने वाले सत्र में 77 प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत ने अगले दो वर्षों के लिए यूनाइटेड किंगडम से चाय पर एफएओ आईजीजी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और सत्र की अध्यक्षता टी बोर्ड इंडिया के उपाध्यक्ष सौरव पहाड़ी ने की। लिए गए प्रमुख निर्णयों में CITS के मुख्यालय को चीन से भारत में स्थानांतरित करना था, जिसे पहले आईजीजी बैठक के प्रस्ताव के अनुसार स्थापित किया गया था। केंद्र और असम सरकार ने चाय पर आईजीजी को छोटे धारकों के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बैठक में एफएओ के आदेश के अनुसार 2022-31 की अवधि के लिए समूह के लिए रणनीतिक ढांचे पर भी चर्चा हुई।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं कि पर्यावरण निकाय जीवंत रूप से कार्य करें, और उन्हें मजबूत बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं कि पर्यावरण निकाय जीवंत रूप से कार्य करें, और उन्हें मजबूत बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए। अदालत ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को अपने कामकाज में संस्थागत पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय अपनाने का निर्देश दिया। इसने CEC को अपने कार्यों और आंतरिक बैठकों के संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। न्यायालय का निर्णय CEC के संस्थागतकरण और पुनर्गठन के संदर्भ में था। इसके संचालन और आंतरिक बैठकों के लिए दिशानिर्देश CEC द्वारा विकसित किए जाएंगे। सीईसी सचिव और उसके सदस्यों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करने वाली संचालन प्रक्रियाएं CEC द्वारा विकसित की जानी चाहिए। CEC को सार्वजनिक बैठकों के लिए दिशानिर्देश बनाने चाहिए, अपनी वेबसाइट पर पहले से एजेंडा प्रकाशित करना चाहिए, बैठक के मिनट्स बनाए रखने चाहिए और पार्टियों को नोटिस देने के लिए नियम स्थापित करने चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3-4 फरवरी, 2024 को ओडिशा और असम का दौरा किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3-4 फरवरी, 2024 को ओडिशा और असम का दौरा किया। 3 फरवरी को, प्रधान मंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखी। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई

परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास ओडिशा के संबलपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम में किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 'जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (JHBDPL)' के 'धामरा - अंगुल पाइपलाइन खंड' (412 किलोमीटर) का उद्घाटन किया। 'प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा' के तहत 2450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित यह परियोजना ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा पाइपलाइन के 'नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड' (692 किलोमीटर) की आधारशिला भी रखी। 2660 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना से ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में सुधार होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 28,980 करोड़ की कई बिजली परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने 27000 करोड़ से अधिक की नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) तालाबीरा थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने 'डिजिटल इंडिया फ्यूचरलैब्स समिट 2024' में "डिजिटल इंडिया फ्यूचरलैब्स" लॉन्च किया।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास और उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने 'डिजिटल इंडिया फ्यूचरलैब्स समिट 2024' में "डिजिटल इंडिया फ्यूचरलैब्स" लॉन्च किया। NXP सेमीकंडक्टर, टेनस्टोरेट और क्वालकॉम इंडिया जैसी कंपनियों ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग स्पेस, कंप्यूट स्पेस में डिजाइन और इनोवेशन और भारतीय टेलीकॉम स्टैक जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया जिसमें प्रमुख उद्योग के खिलाड़ियों, स्टार्टअप, युवा भारतीयों और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के शिक्षाविदों के वरिष्ठ नेतृत्व शामिल थे। सी-डैक द्वारा समन्वित डिजिटल इंडिया फ्यूचरलैब्स का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत ट्रिलियन-डॉलर के अवसर का लाभ उठाना है।

तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम वर्तमान 'टीएस' से बदलकर 'टीजी' करने का निर्णय लिया।

तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम वर्तमान 'टीएस' से बदलकर 'टीजी' करने का निर्णय लिया। यह निर्णय मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसले के बाद, केंद्र सरकार के राजपत्र में 'टीजी' 'टीएस' की जगह लेगा। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद, तत्कालीन टीआरएस सरकार ने राज्य के संक्षिप्त नाम के रूप में 'टीएस' चुना था। कैबिनेट ने तेलंगाना के लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए तेलंगाना तल्ली प्रतिमा को बदलने का भी निर्णय लिया। इसने एंड्रेसरी के 'जय जय हो तेलंगाना' को राज्य गीत के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। सभी हितधारकों के परामर्श से एक नया राज्य प्रतीक डिजाइन करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने 8 फरवरी से

विधानसभा सत्र आयोजित करने का फैसला किया और राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी. विधानसभा में चर्चा के बाद दो और गारंटी लागू की जाएंगी। ये गारंटी हैं 500 रुपये में गैस सिलेंडर और घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। कैबिनेट ने राज्य में जाति जनगणना कराने का भी फैसला किया।

शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूरदराज के गांवों में सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) का उपयोग करके स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (Automated Permanent Academic Account Registry or APAAR) लॉन्च की।

शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूरदराज के गांवों में सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) का उपयोग करके स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (Automated Permanent Academic Account Registry or APAAR) लॉन्च की। APAAR का लक्ष्य 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' नामक एक एकीकृत छात्र पहचान प्रणाली स्थापित करना है। APAAR राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) का हिस्सा है, जिसके लिए सभी कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। नए नियम के तहत, कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एबीसी आईडी रखना अनिवार्य है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने देश में बढ़ती डिजिटल सेवाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि वे सीएससी के माध्यम से स्कूली शिक्षा को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)" को मंजूरी दे दी।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)" को मंजूरी दे दी। इस योजना का लक्ष्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक अगले चार (4) वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन सूक्ष्म और लघु उद्यमों का समर्थन करना है। उप-योजना को 6,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय पर PMMSY के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें विश्व बैंक और एएफडी बाहरी वित्तपोषण सहित 50% यानी 3,000 करोड़ रुपये का सार्वजनिक वित्त शामिल होगा। और शेष 50% यानी 3,000 करोड़ रुपये लाभार्थियों/निजी क्षेत्र के उत्तोलन से प्रत्याशित निवेश है। इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के लिए कवरेज में

सुधार के लिए 96,317.65 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के लिए कवरेज में सुधार के लिए 96,317.65 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दी। संचार मंत्रालय ने 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की घोषणा की है। उक्त स्पेक्ट्रम 20 वर्षों की वैधता अवधि के साथ पेश किया जाएगा। कुल 10,523.15 मेगाहर्ट्ज की पेशकश 96,317.65 करोड़ रुपये के मूल्यांकन के साथ की जा रही है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने वार्षिक NeSDA Way Forward Report 2023 जारी की है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने वार्षिक NeSDA Way Forward Report 2023 जारी की है। रिपोर्ट अनिवार्य ई-सेवाओं और NeSDA फ्रेमवर्क के तहत कुल ई-सेवाओं के तहत वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालती है। ई-सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने क्रमशः भोपाल, मुंबई और गुवाहाटी में तीन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए, जिन्हें डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (पीपी) और राज्य सरकारों के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। विभाग ने ई-सेवा वितरण में सुधार के लिए RTS आयुक्तों/अपीलीय अधिकारियों के साथ भी काम किया। इसने उभरती और भविष्य की ई-गवर्नेंस पहल और उभरती प्रौद्योगिकियों के विषय पर उद्योग जगत के नेताओं के साथ विचार-मंथन सत्र का भी आयोजन किया।

चिली के दो बार के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है।

चिली के दो बार के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मिगुएल जुआन सेबेस्टियन पिनेरा इचेनिक चिली के एक व्यापारी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 2010 से 2014 तक और फिर 2018 से 2022 तक चिली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फोर्ब्स के अनुसार, उनकी मृत्यु के समय उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिससे वह चिली के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 1177वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।

प्रमुख ब्रिटिश-भारतीय सहकर्मी श्रीला फ्लेथर का 89 वर्ष की आयु में ब्रिटेन में निधन हो गया।

प्रमुख ब्रिटिश-भारतीय सहकर्मी श्रीला फ्लैथर का 89 वर्ष की आयु में ब्रिटेन में निधन हो गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी खूबसूरत साड़ियों के लिए जानी जाने वाली, शिक्षिका और राजनीतिज्ञ बर्कशायर में विंडसर और मेडेनहेड की बैरोनेस फ्लैथर के रूप में जीवन साथी थीं। मेमोरियल गेट्स काउंसिल के आजीवन अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान लगभग 5 मिलियन राष्ट्रमंडल सैनिकों द्वारा किए गए युद्ध प्रयासों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में लंदन के हाइड पार्क कॉर्नर में प्रतिष्ठित मेमोरियल गेट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक अद्वितीय व्यक्तित्व और प्रकृति की शक्ति थीं। श्रीला को हमेशा भारतीय और एशियाई होने पर गर्व था।

प्रसिद्ध साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान का 78 वर्ष की आयु में पटना, बिहार में निधन हो गया।

प्रसिद्ध साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान का 78 वर्ष की आयु में पटना, बिहार में निधन हो गया। खान के साहित्यिक योगदान ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई, जिसमें 2015 में पद्म श्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार, दिनाकर राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत-भारती जैसे प्रतिष्ठित सम्मान शामिल हैं। उनके उल्लेखनीय कार्यों में उनका मैथिली उपन्यास 'भामती: एक अविस्मरनिया प्रेमकथा' शामिल है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उनका हिंदी उपन्यास 'सिरजनहार', जिसके लिए उन्हें 2012 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से कुसुमांजलि साहित्य सम्मान मिला।

अनुभवी प्रसारक, कवि और साहित्य अकादमी विजेता मीर मोहम्मद फारूक नाज़की का 83 वर्ष की आयु में कटरा में निधन हो गया।

अनुभवी प्रसारक, कवि और साहित्य अकादमी विजेता मीर मोहम्मद फारूक नाज़की का 83 वर्ष की आयु में कटरा में निधन हो गया। नाज़की ने ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और 1995 में, नाज़की को उनकी कविता पुस्तक नार ह्युटुन कंज़ल वानास (फायर इन द आईलैशेज़) के लिए कश्मीरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह दो मुख्यमंत्रियों - फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला - के मीडिया सलाहकार भी थे। फारूक नाज़की का जन्म 1940 में हुआ था। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने कश्मीरी दस्तकारियाँ और लफ़्ज़ जैसे रत्नों का निर्माण किया। उन्होंने 1986 से 1997 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय (भारत) के तहत दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर श्रीनगर (एआईआर श्रीनगर) के निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने दुनिया के महासागरों और वायुमंडल का बारीकी से अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया PACE उपग्रह लॉन्च किया है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने दुनिया के महासागरों और वायुमंडल का बारीकी से अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया PACE उपग्रह लॉन्च किया है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से PACE को कक्षा में पहुंचाया। PACE का मतलब Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem है। उपग्रह पृथ्वी की सतह से 676 किलोमीटर ऊपर की कक्षा से पर्यावरण का अध्ययन करने में कम से कम तीन साल बिताएगा। एक तीसरा उपकरण मासिक माप एकत्र करेगा। वैज्ञानिकों को अपना पहला डेटा एक या दो महीने के भीतर मिलना शुरू हो जाना चाहिए।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) ने मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन पहल तकनीकी हस्तक्षेप (NITISH) डिवाइस लॉन्च किया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) ने मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन पहल तकनीकी हस्तक्षेप (Novel Initiative Technological Intervention for Safety of Humanlives or NITISH) डिवाइस लॉन्च किया है। यह एक अभिनव पेंडेंट-आकार की तकनीक है, जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, विशेष रूप से बिजली, बाढ़, हीटवेव और कोल्डवेव को लक्षित करने के लिए। यह उपकरण बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र से जुड़ा है, जो वास्तविक समय और सटीक मौसम संबंधी अलर्ट सुनिश्चित करता है। NITISH डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), पटना, बिहार के सहयोग से पेश किया गया है।

एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने भारतीय वायु सेना (IAF) के मध्यम परिवहन विमान (MTA) खरीद परियोजना के लिए C-390 मिलेनियम बोली पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) की घोषणा की है।

एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने भारतीय वायु सेना (IAF) के मध्यम परिवहन विमान (MTA) खरीद परियोजना के लिए C-390 मिलेनियम बोली पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) की घोषणा की है। 9 फरवरी को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित एमओयू के हिस्से के रूप में, एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अध्यक्ष और सीईओ बॉस्को दा कोस्टा जूनियर के अनुसार, एम्ब्रेयर और महिंद्रा "संयुक्त रूप से MTA कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे"। एमओयू का उद्देश्य भारतीय वायु सेना द्वारा अपनी आगामी एमटीए खरीद परियोजना में C-390 मिलेनियम मल्टी-मिशन विमान के अधिग्रहण को संयुक्त रूप से पूरा करना है।

शिक्षा मंत्रालय ने भारत भर के स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) के साथ साझेदारी की है।

शिक्षा मंत्रालय ने भारत भर के स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) के साथ साझेदारी की है। उनकी संयुक्त पहल का लक्ष्य 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में 11 लाख फुटबॉल वितरित करना है, जिससे यह खेल देश भर में छात्रों के लिए सुलभ हो सके। इस पहल का उद्देश्य फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करना है, जिसमें लिंग की परवाह किए बिना समावेशिता पर जोर दिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अंडर-19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया।

दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अंडर-19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। 2024 आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था, जो 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। यह अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का 15वां संस्करण था।

भारत और बांग्लादेश को 8 फरवरी, 2024 को ढाका, बांग्लादेश के BSSSMK स्टेडियम में SAFF U19 महिला चैम्पियनशिप का संयुक्त चैंपियन घोषित किया गया।

भारत और बांग्लादेश को 8 फरवरी, 2024 को ढाका, बांग्लादेश के BSSSMK स्टेडियम में SAFF U19 महिला चैम्पियनशिप का संयुक्त चैंपियन घोषित किया गया। 2024 SAFF अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप SAFF U-18/19/20, महिला चैम्पियनशिप का पांचवां संस्करण था, जो SAFF द्वारा आयोजित महिलाओं की अंडर-19 राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता थी। यह टूर्नामेंट 2 से 8 फरवरी 2024 तक बांग्लादेश में आयोजित किया गया था।

असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स - 2023, अष्टलक्ष्मी का लोगो, गान, शुभंकर, जर्सी और मशाल लॉन्च किया।

असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स - 2023, अष्टलक्ष्मी का लोगो, गान, शुभंकर, जर्सी और मशाल लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक भी मौजूद थे. उद्घाटन समारोह 19 फरवरी को होगा और कुल 20 खेल आयोजनों में से 16 गुवाहाटी में आयोजित किये जायेंगे। बाकी विधाओं की प्रतियोगिताएं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में आयोजित की जाएंगी। असम सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से, इस महीने की 19 से 29 तारीख तक गुवाहाटी में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करने जा रही है। यह कार्यक्रम 11 दिनों की अवधि के दौरान 7 शहरों में 18 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जहां 20 खेल विषयों में लगभग

4500 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। मेगा-यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में 200 से अधिक विश्वविद्यालय भाग लेंगे।